

नक्शा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन में शहरी बस्तियों के [भूमि सर्वेक्षण](#) के लिये नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु

- नक्शा कार्यक्रम के बारे में
 - [डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#) के तहत "नक्शा" (NAKSHA - National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
 - इस पहल के अंतर्गत 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिनमें मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर (शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), वदिशा, सांची, उन्हेल) भी शामिल हैं।
- उद्देश्य
 - इस पहल का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना और सटीक भू-स्थानिक डाटा पर आधारित एक व्यापक [भूमि प्रबंधन प्रणाली](#) विकसित करना है।
 - यह पहल:
 - नागरिकों को सशक्त बनाएगी और उनके जीवन को सुगम बनाएगी।
 - शहरी नियोजन में सुधार लाने में सहायक होगी।
 - भूमि संबंधी विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
 - आईटी-आधारित संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता एवं [सतत विकास](#) को बढ़ावा देगी।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

- परिचय:
 - केंद्र सरकार ने 21 अगस्त, 2008 को देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) मंजूरी दी थी, जिसे वर्ष 2016 में पुनः आरंभ किया गया और इसका नाम बदलकर [डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम \(DILRMP\)](#) कर दिया गया।
 - यह केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- उद्देश्य:
 - अद्यतन भूमि अभिलेखों, संचालित और स्वचालित उत्पत्ति, पाठ्य और स्थानिक अभिलेखों के बीच एकीकरण, राजस्व एवं पंजीकरण के बीच अंतर-संयोजन, वर्तमान विलेख पंजीकरण तथा प्रकल्पित शीर्षक प्रणाली को शीर्षक गारंटी के साथ नरिणायक शीर्षक के साथ बदलने के लिये एक प्रणाली की शुरुआत करना।